Cases of corruption in MCDs

*181. SHRI VIJAY GOEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether several cases of corruption have been reported in all the three Municipal Corporations of Delhi (MCDs) during last three years;

(b) if so, the total number of such cases reported and the action taken against the guilty during each of the last three years;

(c) the number of cases solved/unsolved and the steps taken to solve all the pending cases during the said period; and

(d) the steps taken to weed out corruption in MCDs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIBHAI PARTHIBHAI CHAUDHARY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The superintendence, control and direction of Municipal Corporations of Delhi largely rests with the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD).

Based on the information provided by the MCDs, details of cases and action taken against the delinquent officials during last 3 years are given in the Statement-I (*See* below). The cases with CBI/ACB are given in the Statement-II (*See* below).

(d) The Municipal Corporations have reported that they are taking various steps to weed out corruption including:

(i) Introduction of biometric system of attendance.

(ii) Introduction of e-tendering to maintain transparency in procurement.

(iii) Introduction of special task force to carry out multifarious inspections.

(iv) Introduction of a toll free telephone to invite complaints in order to bring effective changes and improvements in working of the MCDs.

(v) A systemic improvement in the process for sanction of building plans has been done.

(vi) Redressal of grievances in personal interface between the complainant and senior officers of concerned Zones/Departments.

(vii) Sampling and testing of RCC works, cement mortar and wooden shutters to cross-check the quality.

Statement-I

Details of action taken against the delinquent officials of Municipal Corporations of Delhi from January, 2013 to December, 2015

	Year	No. of cases reported	No. of cases investigated	No. of RDA Registered	No. of RDA cases finalised	No. of pending RDA cases	No. of officials involved	No. of officials penalized	No. of officials exonerated	No. of officials involved in pending RDA cases
North DMC	2013	46	28	23	04	19	54	06	05	43
	2014	140	63	29	03	26	49	03	02	44
	2015	178	110	42	06	36	75	08	02	65
TOTAL		364	201	94	13	81	178	17	09	152
South DMC	2013	78	45	17	05	12	22	02	04	16
	2014	81	41	12	02	10	22	01	03	18
	2015	97	43	13	01	12	22	Nil	01	21
TOTAL		256	129	42	08	34	66	03	08	55
East DMC	2013	282	96	18	04	14	32	01	04	27
	2014	194	123	16	02	14	32	01	04	27
	2015	236	81	24	02	22	54	02	01	51
TOTAL		712	300	58	08	50	118	04	09	105

Statement-II

Details regarding cases with CBI/ACB

Year	Cases registered with CBI and ACB			Officials booked		
	CBI	ACB	Total	CBI	ACB	Total
			2013			
North DMC	06	02	08	25	04	29
East DMC	Nil	01	01	Nil	01	01
South DMC	07	02	09	14	02	16
TOTAL	13	5	18	39	7	46
			2014			
North DMC	03	02	05	04	02	06
East DMC	03	05	08	05	05	10
South DMC	04	01	05	06	02	08
TOTAL	10	8	18	15	9	24
			2015			
North DMC	—	02	02	—	05	05
East DMC	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
South DMC	03	01	04	03	01	04
TOTAL	3	3	6	3	6	9

श्री विजय गोयलः सभापति जी, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। बीसियों सालों से एमसीडी को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को अफसर लोग चला रहे हैं। यह ठीक है, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली या सिविक बॉडीज़ में जो भ्रष्टाचार होता है, उसको रोकने के लिए नक्शे ऑनलाइन हो रहे हैं, ई-टेंडरिंग हो रही है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन हो रहा है, बायोमीट्रिक सिस्टम लग रहा है, complaint सेंटर्स खोले जा रहे हैं, फिर भी आप देखिए कि superintendence, control और डायरेक्शन ऑफ एमसीडी की जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट की है, लेकिन इसको ठीक तरह से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। यहां जो आंकड़े दिए गए हैं, इनमें नॉर्थ कॉरपोरेशन के अंदर 364 cases थे, लेकिन जो cases finalise किए हैं, वे 13 हैं, साउथ एमसीडी कॉरपोरेशन में करप्शन के 256 cases थे, उनमें से केवल 8 finalise किए, ईस्ट दिल्ली कॉरपोरेशन में 712 cases थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 finalise किए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आपका सवाल क्या है?

श्री विजय गोयलः मैं सवाल कर रहा हूं। 1332 cases में से सिर्फ 29 cases, जो अफसरों के खिलाफ हुए, उनमें उनको पकड़ा गया या छोड़ा गया, यह भी मालूम नहीं है। मेरा सवाल यह है कि इसको अफसर चला रहे हैं और मेयर्स के पास कोई पावर नहीं है। अगर हमें ध्यान हो तो 1915 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेयर-इन-काउंसिल के सबसे पहले मेयर थे। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Question, please.

श्री विजय गोयलः सभापति जी, मेरा यह सवाल है कि जब चुने हुए प्रतिनिधि, मेयर्स और दूसरे प्रतिनिधियों के पास पावर ही नहीं है, तो इन पर चेक कैसे रखा जाएगा? क्या मंत्री जी मेयर-इन-काउंसिल बनाने पर विचार करेंगे ताकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास पावर आए और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति जी, एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन है। हमारे माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या मेयर-इन-काउंसिल लाएंगे या नहीं, उस संदर्भ में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा, तब हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन आज तक हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री सभापतिः थैंक यू, दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री विजय गोयलः सभापति जी, एमसीडी के अंदर यह जरूरी है। इसका पहले तीन कॉरपोरेशन्स में विभाजन कर दिया गया था। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी कब से तीन कॉरपोरेशन्स को दुबारा से एक करने का प्रस्ताव लाएंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अफसरों के ऊपर अंकुश रखने के लिए सरकार क्या करेगी? अगर दिल्ली सरकार कॉरपोरेशन्स को फंड ही नहीं दे रही है, उनको 500 करोड़ रूपये देने थे, जिसकी वजह से एमसीडी उनको सैलेरी ही नहीं दे पा रही है, इस समस्या के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ताकि एमसीडी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके?

श्री सभापतिः थैंक यू।

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति जी, मैंने पहले भी बताया है कि जो एमसीडी है, वह राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन केंद्र सरकार उनको डायरेक्शन जरूर दे सकती है। यदि कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर बनाना है, तो उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ परामर्श करते हैं, अधिकारियों को भी बुलाते हैं। माननीय सदस्य ने उनकी इंक्वायरीज के बारे में पूछा, तो मैं बताना चाहता हूं कि 1362 cases थे और उनमें से 630 cases के investigations चल रहे हैं। हम राज्य सरकार को डायरेक्शन देने वाले हैं और हम बार-बार बोलेंगे। यदि कोई पर्टिकुलर केस होता है, तो हम उस पर एक्शन भी लेते हैं।

श्री परवेज़ हाशमीः सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक चीज तो यह कही कि MCD दिल्ली राज्य सरकार के अन्दर है। यहां Anti Crime Branch का हेड बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में रोज झगड़े हो रहे हैं। वे इसका हेड नहीं बना पा रहे हैं। LG अपना ACB Head बना कर रखना चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर अपना ACB हेड बनाकर रखना चाहते हैं, जो इस मैटर को देखता है। दूसरा, इसमें सबसे important चीज यह है कि CBI ने 2013 में 13 केस रजिस्टर किए, Anti Crime

Branch ने 5 केस रजिस्टर किए, 2014 में CBI ने 10 किए, Anti Crime Branch ने 8 किए, जो जवाब आया है, मैं उसे पढ़ रहा हूं। 2015 में CBI ने 3 किए, Anti Crime Branch ने भी 3 किए। इसमें 2013 में 46 ऑफिसर्स को book किया गया, 2014 में 24 ऑफिसर्स को बुक किया गया, 2015 में 9 ऑफिसर्स को बुक किया गया। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि CBI और Anti Crime Branch ने कितने ऑफिसर्स को अभी तक convict किया और अगर नहीं किया, तो क्यों नहीं किया?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति महोदय, मैंने इसमें पूरा डिटेल दिया है कि कितने ऑफिसर्स involved हैं, कितनों को penalize किया गया। North MCD में 178 ऑफिसर्स involved थे, इनमें से ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप जवाब सुन लीजिए।

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः मैंने पूरे फिगर्स दिए हैं। अभी भी स्टेट गवर्नमेंट investigation कर रही है। हम इसके ऊपर vigilance रखते हैं, direction देते हैं। हम इसका जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Mr. K. T. S. Tulsi.

SHRI K. T. S. TULSI: Hon. Chairman, Sir, it is a matter of great regret that 300 officials were charged with corruption between 2012 and 2015. This information has been obtained under the Right to Information Act. There are, otherwise, 4,299 cases pending, pertaining to corruption with regard to MCD Vigilance Department and they remain pending for some time. 1,435 cases of Anti Corruption Bureau are pending. 2,877 cases with CBI are pending. How is the Government hoping to tackle the menace of corruption? Delhi and Delhi local bodies are said to be the most corrupt in the country.

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति महोदय, हमारे पास MCD से जो आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार total cases 1,332 हैं। इनमें अभी 630 में जांच चल रही है। जो विभागीय कार्रवाई की जाती है, उनकी संख्या 194 है। विभागीय कार्रवाई में जो final किए गए, उनकी संख्या 29 है। Pending cases 165 हैं, जिनके बारे में हमारे माननीय सांसद महोदय ने बार-बार प्रश्न उठाया है। जो अधिकारी involved हैं, ऐसे 362 अधिकारी involved हैं। जिनको सजा दी गई, ऐसे 24 हैं और निर्दोष 26 हैं। अभी 312 केसेज में inquiry चल रही है। हम इनके ऊपर कड़े कदम उठाएंगे।

Import of edible oil

*182. SHRI C. M. RAMESH: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the year-wise, quantity-wise and country-wise import of edible oil into the country in the last three years;